डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता विकसित करने पर उच्च स्तरीय संवाद में उद्घाटन भाषण *

श्री संजय मल्होत्रा

डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म्स (डीपीपी) के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता विकसित करने पर इस उच्च स्तरीय संवाद में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है।

इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। आपके प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख निर्णय निर्माताओं के रूप में, जिन्हें आपकी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक दशा और सुदृढ़ता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, आज हमारे बीच आपकी उपस्थिति इस अवसर पर अति-महत्वपूर्ण है।

मैं आज के विषय पर एक समृद्ध और उपयोगी चर्चा की अपेक्षा करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारे लोगों के आर्थिक कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता है।

भारत इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे डिजिटल सार्वजनिक मंच (डीपीपी) वास्तविक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं और हमारे नागरिकों के जीवन को भौतिक रूप से बेहतर बना सकते हैं।

I. डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म को औपचारिक रूप से न्यूनतम, मॉड्यूलर डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर निर्मित साझा डिजिटल प्रणाली के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसका उपयोग सरकारों, कारोबारों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज द्वारा समाज-व्यापी विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है।[1]

इन प्लैटफॉर्मों में खुली, सुरक्षित और अंतर-परिचालनीय प्रणालियां शामिल हैं जो सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती हैं। डिजिटल पहचान, भुगतान एवं डेटा एक्सचेंज इसकी नींव के मूलभूत अंग हैं।

जी20 ने मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक व्यापक ढांचा भी स्थापित किया है जो सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशिता, निर्बाध प्रणाली एकीकरण के लिए अंतरपरिचालनीयता, बड़े पैमाने पर अभिनियोजन के लिए मापनीयता, सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षा सहित ऐसे प्लैटफॉर्मों के विकास और कार्यान्वयन को रेखांकित करता है।

II. केंद्रीय बैंकरों के लिए डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म क्यों मायने रखते हैं - प्रेरक शक्ति के रूप में आर्थिक सुदृढ़ता

केंद्रीय बैंकों के लिए डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म का अत्यधिक महत्व है।

केंद्रीय बैंक न केवल आर्थिक सुदृढ़ता के अंतिम संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वे कई देशों में, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान अवसंरचना के संचालन और विनियमन के लिए भी जिम्मेदार हैं जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म एक प्रभावी साधन है। वे सामूहिक रूप से समावेशन की बाधाओं को कम करते हैं और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, विश्व स्तर पर, लगभग 865 मिलियन व्यक्तियों ने वित्तीय संस्थाओं के साथ अपना पहला खाता खोला, जिससे सरकारी अनुदान और सहायता[2] की त्वरित और झंझट-रहित प्राप्ति संभव हो गई।

तीव्र भुगतान प्रणालियों (फास्ट पेमेंट सिस्टम्स - एफपीएस) का विकास प्रमुख सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के साथ संरेखित होता है, जिसमें सभी के लिए सुरक्षित और कुशल भुगतान प्रणाली का निर्माण, नकदी निर्भरता को कम करना और डिजिटलीकरण का समर्थन करना शामिल है। एफपीएस का, संख्या और उपयोग, दोनों में बढ़ना जारी है, जिसे दुनिया भर में 70 से अधिक क्षेत्राधिकारों में स्थापित किया गया है।[2]

III. समावेशी, सुरक्षित और स्केलेबल डीपीपी में एक केस स्टडी के रूप में भारत

भारत के डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म 'आधार' के माध्यम से डिजिटल पहचान, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के

* 14 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन, डीसी में आयोजित डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता विकसित करने पर उच्च स्तरीय संवाद में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का उद्घाटन भाषण।

[1] डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म की प्रणालियों के लिए जी20 फ्रेमवर्क।

2 डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म और विकास: एक विश्व बैंक समूह दृष्टिकोण; मार्च 2025।

माध्यम से तत्काल भुगतान प्रणाली तथा डेटा एम्पॉवरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (डीईपीए) के माध्यम से सुरक्षित डेटा साझाकरण सहित इंटरकनेक्टेड डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक सुसंरचित, बहुस्तरीय प्रणाली का गठन करते हैं।

हमारे लिए, मार्गदर्शक सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ और बिना लाभ के उद्देश्य के सर्व जन सुगम वस्तु के रूप में ऐसे प्लैटफॉर्मों का निर्माण करना रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाएं ऋण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और कई अन्य डोमेन में अनुप्रयोगों को शीघ्र विकसित करने के लिए इन प्लैटफॉर्मों का लाभ उठा सकती हैं।

जबकि सार्वजनिक क्षेत्र मूलभूत अवसंरचना का स्तर स्थापित करता है, डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्मों की सफलता को निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से बल मिलता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी नवोन्मेष को बढ़ावा देती है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र सक्रिय डेवलपर समुदायों का नवोन्मेष और पोषण करने तथा डिजिटल बाजारों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी सुलभता, समावेशिता और लोक हित के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए डीपीपी के आसपास पारितंत्र की परिपक्वता में योगदान करते हैं।

इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक अप्रत्यक्ष लाभ देखने को मिले हैं। मैं इस तरह के प्लैटफॉर्म बनाने के लिए भारत द्वारा की गई कुछ पहलों पर प्रकाश डालूंगा।

मैं 'आधार' से शुरुआत करूंगा, जो विशिष्ट पहचान प्लैटफॉर्म है। यह किसी देश में किसी भी डिजिटलीकरण प्रयास के लिए बहुत ही आधारभूत नींव है। आज 'आधार' के 1.3 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। इस पहचान मंच का उपयोग करते हुए, 566 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, इनमें से 316 मिलियन महिलाओं के हैं। इसने वित्तीय समावेशन पहलों को बहुत महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है।

इसने नकद आधारित सब्सिडी संवितरण को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को भी सक्षम बनाया है और सब्सिडी को सीधे बैंक खातों में जमा किया है। 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई है, जिससे धोखाधड़ी और रिसाव (लीकेज) में काफी कमी आयी है।

भुगतान की बात करें, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई एक अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म है। इसने भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है। यह बैंकों में वास्तविक (अत्यल्प) समय में एक खाते से दूसरे खाते में भुगतान अंतरण को कुशलतापूर्वक सक्षम बनाता है।

आज भारत में लगभग 85 प्रतिशत डिजिटल भुगतान लेनदेन यूपीआई के माध्यम से किए जाते हैं। यूपीआई का उपयोग करके हर महीने लगभग 20 बिलियन लेनदेन किए जाते हैं, जो मूल्य में 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यूपीआई एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है, जो वित्तीय समावेशन को गति देता है। लघु विक्रेता और सूक्ष्म उद्यम अब डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, और वित्तीय इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, जिससे बहुत कम लागत पर औपचारिक ऋण तक पहुंच सक्षम हो सकती है।

इसके अन्य लाभ भी हैं। यूपीआई के प्रभाव पर हाल ही में किए गए एक शोध अध्ययन से पता चलता है कि उच्च यूपीआई अंगीकरण कम नकदी की मांग से जुड़ा है[3]। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि यूपीआई लेनदेन की मात्रा में एक प्रतिशत की वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.03 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित है[4]।

डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने वितरण लागत में कमी लायी है, राजस्व रिसाव को कम किया है, और विशेष रूप से वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत कार्यक्रमों के तेजी से अभिनियोजन की सुविधा प्रदान की है।

IV. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

हमारा विश्वास है कि डीपीपी के लाभ 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से पूरी दुनिया को उपलब्ध होने चाहिए, जिसका अर्थ है, 'विश्व एक परिवार है'। यह भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय

3 नकद मांग पर यूपीआई का प्रभाव – राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर से साक्ष्य, आरबी-आई बुलेटिन, सितंबर 2025।

4 भारत की यूपीआई घटना को डिकोड करना: वैश्विक निहितार्थ के साथ एक डिजिटल क्रांति': ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सितंबर 2024।

भी था। हम ऐसे प्लैटफॉर्मों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

इस सहयोग की भावना में, भारत ने डिजिटल पहचान के लिए मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लैटफॉर्म (एमओएसआईपी)[5] विकसित किया। यह निःशुल्क, सुरक्षित और स्केलेबल प्लैटफॉर्म अन्य देशों को अपने स्वयं के राष्ट्रीय डिजिटल आईडी सिस्टम बनाने की अनुमति देता है। वर्तमान में 27 देश अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाएं शीघ्र, प्रत्यक्ष रूप से और निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए एमओएसआईपी-आधारित प्रणालियों को अपना रहे हैं या उन पर विचार कर रहे हैं।

डिजिटल भुगतान में सहयोग के लिए, हमने तीन रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाए हैं:

i. पहला, हम सीमा-पार विप्रेषण के लिए यूपीआई को दूसरे देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों से जोड़ रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच लिंकेज (UPI-PayNow) अभी लाइव है। कुछ अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से कार्य प्रगति पर है।

ii. दूसरा, हम ऑफलाइन और ई-कॉमर्स माध्यम, दोनों में मर्चेंट स्थानों पर क्यूआर कोड द्वारा यूपीआई के माध्यम से सीमा-पार मर्चेंट (पी2एम) भुगतान को सक्षम कर रहे हैं। यह पहले से ही कुछ देशों में लाइव है तथा कुछ और देशों में व्यापारिक भुगतान को सक्षम करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

iii. तीसरा, हम यूपीआई जैसी सॉवरेन पेमेंट रेल्स के विनियोजन या यूपीआई टेक्नोलॉजी स्टैक का उपयोग करके भागीदार देशों में मौजूदा प्रणालियों को अपग्रेड करने का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ और देशों में विनियोजन के लिए समझौते/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ये प्रयास दक्षता को प्रोत्साहित करने, ग्राहक अनुभव में सुधार करने और लागत को कम करने के साथ-साथ सीमा-पार व्यापार और भुगतान को भी बढ़ावा देंगे।

निष्कर्ष टिप्पणियाँ

अंत में, डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म भारत में समावेशी विकास के केंद्र-बिंदु सिद्ध हुए हैं। कल्याण अंतरण, भुगतान के लोकतंत्रीकरण और वित्तीय समावेशन के गहनीकरण पर उनका प्रभाव वास्तव में परिवर्तनकारी रहा है। हम देशों के लिए डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने में मदद करने के लिए अपने मॉडल को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि हम डिजिटल सार्वजनिक प्लैटफॉर्म के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।

धन्यवाद।

5 'एमओएसआईपी' एक ओपन-सोर्स, गैर-लाभकारी मंच है जो सरकारों को सुरक्षित, स्केलेबल और अनुकूलन योग्य पहचान प्रणालियों के स्वामित्व और संचालन के लिए सशक्त बनाता है।